श्री जगत सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन कमोडिटीज के निर्यात पर इमदाद देने का फैसला किया गया है।

श्री दिनेश सिंह : सभी पर विचार करेंगे।

Shri S. K. Tapuriah: The ever-smiling hon. Minister just now made what he thought was a valuable suggestion to the businessman to export without profits, if need be, for the sake of the country. May I ask him whether, knowing also full well that the prices of our products are very prohibitive, Government will take any steps to at least make raw materials available at international prices so that if the manufacturers or exporters want to export without profit they can do so without loss or at some loss? Could the hon. Minister make raw materials available at international prices?

Shri Dinesh Singh: The hon. Member knows full well that even if we made an attempt to make the raw materials available at international prices, they will not be able to export at international prices, because then they would say that labour is expensive, the cost of production is higher and so on. It is not such an easy question as has been sought to be made out. The hon. Member knows very well that we have discussed this on many occasions, and as I have said in this House, we are discussing commodity-wise with the Export-Import Councils how best we can help them to export.

Expansion of Bhilai Steel Plant

***1293. Shri Ram Kishan Gupta:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to expand the Bhilai Steel Plant in the near future; and

(b) if, so, whether the Russian collaboration and import of materials from Russia involving foreign exchange will be necessary for the expansion?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) Yes, Sir. It is proposed to expand the Bhilai Steel Plant from 2.5 million ingot tonnes capacity to 3.2 million ingot tonnes capacity during the Fourth Plan period.

(b) The expansion is being undertaken with the Russian Collaboration However, maximum utilisation of indigenous equipment, material and technical skill will be made in the proposed expansion

Shri Ram Kishan Gupta: What is the total estimate of the expansion programme and out of it how much will be utilised for foreign exchange?

Dr. Chenna Reddy: It is estimated that there will be two phases in which this expansion has to take place. For the first phase, the estimate is Rs. 287.58 millions with a foreign exchange component of Rs. 91.06 millions. The details of the second phase in regard to the different alternatives are still under examination. So, it is not possible to give a specific figure, but it is estimated that the second phase may cost roughly Rs. 560 millions with a foreign exchange component of Rs 170 millions

Shri Ram Kishan Gupta: How many Russian experts are working there at present?

Dr. Chenna Reddi: For this particular expansion programme, we are only expecting that about 18 people will be required in the first *phase;* even they have not all arrived yet.

श्री महाराज सिंह भारती : रांची का जो पुराना संस्थान है, जो फौलाद की मिलें बनायेगा, वह अपनी क्षमता से 10 फीसदी काम इस लिये कर रहा है कि उसको

आर्डर नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भिलाई की एक्सपैंशन के लिये रांची संस्थान की मशीनरी, जो इस वक्त निठल्ला बैठा हुआ है, क्यों इस्तेमाल नहीं की गई है; इस में क्या दिक्कत है।

डा० चन्ना रेड्डी : यदि रांची संस्थान के मायने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से है तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इस एक्सपैंशन प्रोग्राम के फर्स्ट फेस में हमें जिन चीजों की जरूरत है उस में से सप्लाई आफ़ इक्विपमेन्ट मे 6500 टन सोवियत रशिया से मंगाया जा रहा है, 5700 टन राची से लिया जा रहा है, इस के अलावा स्ट्रक्चरल्ज मे 6900 टन राची हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से लिया जा रहा है। इन के अलावा 4 हजार टन भिलाई स्टील प्लाट वाले हमारे मुल्क में दूसरी जगहों पर इन्डीजिनस बने हुए में से सप्लाई करेंगे।

श्री महाराज सिंह भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि उस संस्थान से सारी मशीनरी पूरी क्यों नही ली जा रही है, क्या वहां बन नहीं सकती हैं, डिजाइन नहीं हो सकती हैं या उन को बनाने वाली मशीनें उपलब्ध नहीं हैं—इसकी वजह बताइये ?

डा० चन्ना रेड्डी : जितनी चीजें यहां बन सकती हैं उन को हम ले रहे हैं। जिनके लिये मजबूरी है, उन को बाहर से मंगाना पड़ रहा है।

श्री महाराज सिंह भारती : मजबूरी क्या है ?

डा० चन्ना रेड्डी : सारी चीजें हम अपने देश में नहीं बना सकते हैं, जिन चीजों को बना सकते हैं, उन को हम ले रहे हैं।

श्री मधु लिमये : कब तक बनाने लगेंगे।

Shri Piloo Mody: I hear that they are going to spend over Rs. 9 crores in foreign exchange. In view of the fact that most of our arrangements with the Soviet Union are on a rupee payment basis, how will this foreign exchange equivalent to Rs. 9 crores be required? Secondly, in view of the fact that there is beginning to be a glut in the market in steel, have Government any programme for phasing out the Bhilai steel plant expansion?

Dr. Chenna Reddi: As regards the Rs. 9 crores worth foreign exchange required, it is for such of those inevitable imports we require including technical skill.

Shri Piloo Mody: From where?

Dr. Chenna Reddi: Whether it is rupee exchange or dollar exchange, it is still foreign exchange.

Shri Piloo Mody: Is the payment in rupees or in foreign exchange?

Dr. Chenna Reddi: It is made in foreign exchange, in roubles.

Shri M. Ansersey: When have we had a rouble agreement?

Dr. Chenna Reddi: We have had a credit agreement on 21 February, 1961. Out of that agreement, this amount is set apart for the Bhilai steel plant.

Shri Piloo Mody: Is the Minister aware that as a result of devaluation, the difference between the rupee and the rouble has become very unfavourable to India?

Mr. Speaker: No, Shri Rabi Ray. He has already asked.

Shri Piloo Mody: He did not answer the phasing out part of the question.

श्री रवि राय : भिलाई कारखाने की बढ़ोतरी के लिये हम रूस से सहायता लेते हैं, इसी तरह दुरगापुर की बढ़ोतरी के

लिये जर्मनी से, दुर्गापुर के लिये ब्रिटेन से बने, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन सरकारी संस्थानों का सम्पूर्ण भारतीयकरण कब होगा कितने सालों में होगा, ताकि उस के बाद विदेशों से कोई सहायता न लेनी पड़े ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस वक्त एक्सपैन्शन प्रोग्राम मे जिन मशीनों की जरूरत है उस मे से 69 परसेन्ट हमारे देश मे बनाई जा रही हैं । पूरी तरह से कब कर सकते हैं— इस के लिये इस वक्त बोलना मेरे लिये मुश्किल है । हो सकता है कि आने वाले चन्द सालों में पूरा काम हो सके । गुजिश्ता चन्द सालो मे जसा आप जानते हैं हम बराबर तरक्की कर रहे हैं, जैसे जैसे यहा बनाते जा रहे हैं, बाहर से मंगाना खत्म करते जा रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस कारखाने के विस्तार में 9 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा आप लगाने वाले हैं परन्तु आपने इस बात का जिक्र नही किया कि वहां पर 16 हजार मजदूर जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं उन के लिये कितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं ? वे लोग बरसात में गर्मी में सर्दी में वहां पर पडे हुए हैं उन के मकानो के लिये आप कितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं ?

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नही आया । कारखाने को चलाने वाले लोगो के लिये जो खून पसीना एक करते हैं जिनके सहारे कारखाना चलता है उन के लिये चौथी योजना में कितना खर्च करने वाले हैं ?

Mr. Speaker: He cannot answer that question.

श्री रामावतार शास्त्री : भिलाई कारखाने का इन्तजाम सोवियत रूस के लोगों के हाथ में है जिसकी वजह से वहां पर उत्पादन बढ़ रहा है । लेकिन स्टील के जो दूसरे कारखाने हैं उन का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि वहां उत्पादन न बढ़ने का क्या कारण है तथा क्या सरकार भिलाई की तरह का प्रबन्ध दूसरे कारखानों में भी करना चाहती है ? यदि हां तो कब से ?

डा० चन्ना रेड्डी: दूसरे स्टीलप्लाट्स जैसे जैसे एक्सपैंशन का काम होता है प्रोडक्शन में इन्टरनल इन्हेरेंट कैपेसिटी को हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह प्लाट जिसका एक्सपेंशन आप कर रहे हैं इस के प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वह आप ने रशिया से बनवाई है इस पर कितना खर्च आया है ? क्या यह सही है कि किसी इण्डियन फर्म ने भी आपसे कहा था कि जो खर्च आपने रशिया पर किया है उस से बीसवा हिस्सा कम खर्च यहा लगेगा ? क्या ऐसी कोई आफर आपके पास आई थी लेकिन फिर भी आपने रशिया से ही प्रोजक्ट रिपोर्ट बनवाई । यहीं पर प्रोजैक्ट रिपोर्टस बनें इस के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं तथा बाहर से जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट मगवाते हैं वे गलत होती हैं या सही होती हैं इस की कोई जाच आप करवाते हैं ।

डा० चन्ना रेड्डी : भिलाई के एक्सपेंशन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिलाई के डिजाइन तथा प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तयार की थी जोकि सैन्ट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो राची का एक हिस्सा है । गिपरोमेज़ से भी इस काम मे सलाह ली गई थी और उनकी सलाह मे इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा किया गया है लेकिन पूरा काम हमारे ब्यूरो ने किया है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन को इस के लिये कितना रुपया दिया गया ?

डा० कमा रेड्डी : यह डिटेल्स मेरे पास नहीं है अभी पूरी कीमत नहीं दी गई है।

श्री कंवर लाल गुप्त : बताया गया है कि 40 लाख रुपया आप दे चुके हैं।

डा० कमा रेड्डी : 40 लाख रुपया नहीं दिया है उस का पूरा काम हमारे पब्लिक सेक्टर आर्गेनाइजेशन के ब्यूरो ने किया है।

Mr. Speaker: Next question.

Shri S. M. Joshi *rose*—

Mr. Speaker: No, Shri Rabi Ray. next question. How can I call you? Mr. Hem Barua wanted, Mr. Tapuriah wanted to put a question. If I allow only one and not allow the other, I will be found fault with.

Agitation by All India Railwaymens' Federation

*1294. **Shri S. M. Banerjee:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the decision taken by the All India Railwaymen's Federation in its Working Committee meeting held in Bombay on the 4th and 5th May, 1967 to start agitation;

(b) if so, the demands on which the agitation is likely to be started; and

(c) the steps taken by Government to meet those demands?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Parimal Ghosh): (a) and (b). Yes Sir. According to a resolution passed by the Working Committee of the All India Railwaymen's Federation, the Government was considered to have failed to honour their commitment for grant of automatic rise in dearness allowance. Accordingly the Working Committee directed the affiliated Unions to observe "DEARNESS ALLOWANCE DAY" on 19.5.67 all over the country by holding meetings, taking out processions, wearing badges and issuing pamphlets etc.

(c) The report of the Gajendragadkar Commission on dearness allowance is under consideration of Government and an exchange of views thereon has also recently taken place with States' Chief Ministers. Decisions are expected to be taken in the near future and will be equally applicable to the railway employees.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Minister is fully aware, more than me, that the report of the Gajendragadkar Commission is not being considered at all by the hon. Finance Minister who is not hearing me. So, I would like to know from the Hon. Minister whether, in view of this mounting discontent among the railwaymen throughout the country, this has been brought to the notice of the Finance Minister, to see that proper discussion takes place between the representatives of All India Railwaymen's Federation and the officials on the question of the DA commission report.

Shri Parimal Ghosh: We cannot take a unilateral decision in this matter. The matter has already been stated on the floor of the House by the Deputy Prime Minister and the Finance Minister that he was considering the matter and having discussions with the State Chief Ministers also. As soon as some sort of a decision is taken, whatever the decision, it will be announced on the floor of the House, whatever may be the decision, retrospective effect of the same will be given to the railwaymen also.

Shri S. M. Banerjee: Is he aware that one of the long outstanding demands of the railwaymen is the appointment of a wage board? Several times this was raised on the floor